मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल से राजभवन में मंगलवार को उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेरन पटेल ने सौजन्य भेंट की। वहीं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने राजभवन में श्रीमती पटेल से मुलाकात की। डॉ. यादव ने राज्यपाल श्री पटेल से भी सौजन्य भेंट की। उधर, राज्यपाल श्री पटेल से पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री लखन पटेल ने भेंट की।

प्रकृति से जो पाया है उसे लौटाने का प्रयास है पौधरोपण: डॉ.यादव

मुख्यमंत्री ने निष्ठा परिसर में लगाया आंवले का पौधा, ऊर्जा विभाग के शुभंकर का किया लोकार्पण

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पौधरोपण के लिए आरंभ किया गया, एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और वसुंधरा को संवारने के उनके मन के भाव और संकल्प का प्रकटीकरण है।

पौधरोपण का यह अभियान, परमात्मा से प्रकृति के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है, उसे वापस लौटाने का एक प्रयास भी है। विकास के क्रम में हुए प्रकृति के क्षरण की प्रतिपूर्ति करने और संतुलन बनाए रखने में भी पौध-रोपण से मदद मिल रही है। डॉ. यादव ने पौध-रोपण के एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम अंतर्गत ऊर्जा विभाग के गोविंदपुरा स्थित निष्ठा परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने परिसर में आंवले का पौधा भी लगाया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महापौर श्रीमती मालती राय तथा अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित थे। डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति मातृ-सत्ता की उपासक है और पौध-रोपण अभियान को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने माँ का नाम देकर प्रत्येक व्यक्ति को अभियान से आत्मीय रूप से जोड़ा है। माँ के नाम से अथवा उनकी स्मृति में पौधा लगाना इस बात का भी प्रतीक है कि हमने जो प्रकृति से पाया है, उसे लौटाने का भी हमारे मन में भाव हैं। भारतीय संस्कृति वृक्षों को बहुत महत्व प्रदान करती है, ब्रह्म पुराण में एक वृक्ष को दस पुत्रों के बराबर मानना इस बात का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऊर्जा विभाग द्वारा जारी (बालक-विद्युत और बालिका-बिजली) शुभंकर का लोकार्पण भी किया। डॉ. यादव को इस अवसर पर वृक्ष स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। श्री तोमर ने भी निष्ठा परिसर में आंवले का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान में ऊर्जा विभाग के प्रदेश में स्थित विभिन्न परिसरों में पौध-रोपण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। डॉ. यादव द्वारा किए गए पौध-रोपण के साथ गोविंदपुरा स्थित निष्ठा परिसर में एक सौ पौधे एवं प्रदेश में एक लाख पौधे रोपे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पौधरोपण में सहभागिता के लिए श्री तोमर ने आभार व्यक्त किया।

स्पेस टेक्नोलॉजी में मध्यप्रदेश ने पहली बार निवेश के लिए बढ़ाया कदम

बेंगलुरु में 7 एवं 8 अगस्त को निवेशकों से करेगें संवाद

भोपाल (काप्र)।

राज्य की विकास योजनाओं में नवीन तकनीक की सहायता लेने और उपयोग बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश पहली बार स्पेस टेक कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में मध्यप्रदेश में पहली बार निवेश प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाया है।

स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही कंपनियां उपग्रह चित्रण और डाटा एनालिटिक्स की सेवाएं उपलब्ध कराती है। उपग्रह के माध्यम से वैश्विक निगरानी और डाटा की शुद्धता में सुधार होता है। यह कंपनियां अंतरिक्ष में प्रदूषण और कक्षीय वस्तुओं पर निगरानी के लिए नवीनतम तकनीकी विकसित कर रही है। इन कंपनियों का उद्देश्य अंतरिक्ष में सुरक्षा को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री बेंगलुरु में आयोजित निवेशको के साथ 7 एवं 8 अगस्त को आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर रोड-शो में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। वे इस क्षेत्र में काम कर रही प्रमुख कंपनियों को मध्यप्रदेश में निवेश का आमंत्रण देंगे। इनमें मुख्य रूप से पिक्सल, दिगंतरा, गैलेक्स आई, सेटस्योर कलाइड ईओ, स्काई सर्वर जैसी कंपनियों से मध्यप्रदेश में निवेश की संभावना पर चर्चा करेंगे। सेटस्योर कंपनी सैटेलाइट इमेजरी उपलब्ध कराती है जो कृषि क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार पिक्सल कंपनी पृथ्वी के चित्रों पर आधारित छोटे सैटेलाइट का निर्माण और संचालन करती है। मुख्यमंत्री आईटी सेक्टर की कंपनियों से भी संवाद करेंगे और निवेश की संभावना पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्य रूप से कॉग्निजेंट, नेसकॉम, किंड्रील, इंफोसिस, टीसीएस, विसेन टेक्नोलॉजी, सीसा इंफोसेक हैपिएस्ट माइंड्स, डेल्टा कैपिटा, नीमन मारकस एवं मोवाटे जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे।

इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने वैश्विक ऑपरेशन को बेहतर तरीके से संचालन करने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थपित करती है। यह सेंटर आर्थिक प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, आईटी सपोर्ट, डाटा एनालिटिक्स और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की सेवाएं और संचालन की दक्षता प्रदान करते हैं। वे लागत में कमी लाने में भी मदद करते हैं और स्थानीय बाजार में निवेश के अवसर सृजन करने में सहायक होते हैं। डॉ. यादव की मंशा है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को भोपाल और इंदौर में स्थापित करें। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इन केंद्रों की स्थापना से राज्य की प्रतिभाओं का उपयोग किया जा सकेगा जिससे कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इन केंद्रों से शहरों में तकनीकी नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में आईटी के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों और इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के संबंध में प्रमुख निवेशकों से चर्चा करेंगे। मध्यप्रदेश में गारमेंट इंडस्ट्री की संभावनाओं को देखते हुए बेंगलुरु में प्रमुख परिधान और वस्त्र कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र की कई कंपनियां जैसे बेस्ट कॉर्प और गोकलदास मध्यप्रदेश में निवेश कर रही है। गारमेंट इंडस्ट्री में निवेश से मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। गारमेंट इंडस्ट्री में निवेश से मध्यप्रदेश को युनिवर्सल गारमेंट सेक्टर में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों, आईटी सेक्टर में निवेश, पर्यटन, एमएसएमई में निवेश और गारमेंट सेक्टर में मप्र में बनी संभावनाओ से निवेशकों को परिचित कराया जाएगा।

खाद्य मंत्री के निर्देश पर सॉफ्टवेयर बदलने से आपूर्ति निगम को करोड़ों की बचत

भोपाल (काप्र)। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये जरूरी उपाय करने के निर्देश पर निगम द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है।

मप्र खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सॉफ्टवेयर के स्थान पर अपनी जरूरत के अनुसार एनआईसी से बनवाये गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इससे निगम को करोड़ो रूपये की बचत होगी।मप्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिलों के द्वारा प्रेषित धन मांग-पत्र एवं उनको राशि उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता था। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिलों को राशि उपलब्ध कराने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने में जहां एक ओर अत्याधिक समय लगता था वहीं दूसरी ओर बैंक के खातों में राशि रखने के कारण उस पर ब्याज के रूप में निगम को अनावश्यक वित्तीय भार वहन करना पड़ता था। प्रबंध संचालक आपूर्ति निगम पीएन यादव ने बताया है कि इस समस्या का समाधान निगम द्वारा एनआईसी से विकसित कराये गये ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराया गया है। इसके कारण जिलों की मांग एवं उन्हें राशि उपलब्ध कराने की संपूर्ण प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफी कमी आई है। साथ ही जिला स्तर पर अनावश्यक राशि रखने के कारण होने वाले ब्याज के व्ययभार से बचत की स्थिति निर्मित हुई है। अन्य संसाधनों की भी बचत हुई है। एनआईसी के द्वारा विकसित किया गया साफ्टवेयर ओटीपी आधारित होने के कारण ज्यादा सुरक्षित है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिलों द्वारा की जा रही मांग को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न राइडर्स लगाये गये हैं। विभिन्न कार्यालयीन व्यय जैसे टैक्सी किराया, स्टेशनरी, टेलीफोन, कम्प्यूटर रख-रखाय व्यय एवं विभिन्न आकस्मिक व्यय पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। निगम द्वारा किये गये इन बदलावों से करोड़ो रूपये की वार्षिक बचत होना संभावित है।

प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलाएं : विजयवर्गीय

भोपाल (काप्र)।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिये नगरीय निकायों में कैडरवाइज रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लायें।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में समृद्ध वन हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग मध्यप्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने में श्रेष्ठ कार्य करते हुए इसे ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलाने की ठोस पहल करे। श्री विजयवर्गीय आज भोपाल में मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी भी मौजूद थीं। बैठक में विभाग के संकल्प पत्र की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। श्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिये कि भोपाल एवं इंदौर में महानगरीय सेवाओं को सुदृढ़ किया जाये। इन शहरों के आसपास के नगरों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिये मैट्रोपोलिटन अथॉरिटी के जरिये काम किये जाये। बैठक में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये अलग से संचालनालय गठित करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। अग्निशमन सेवा में आधुनिकीकरण के लिये केन्द्र सरकार से करीब 300 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। साथ ही राज्य का अंश 100 करोड़ रूपये का है। राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटना के दौरान ऐसे वाहनों की सेवा ली जाये, जो खेतों और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुँच सकें। श्री विजयवर्गीय ने शहरी क्षेत्रों में रजक समुदाय के लिये समर्पित लॉन्ड्री क्षेत्र आवंटित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 5 महानगरों में भूमि चिन्हित कर इस कार्य की शुरूआत की जाये। नगरीय निकायों द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय रसोई घर केन्द्रों की संख्या अब बढ़कर 191 हो गई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख 92 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।

प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि आगामी 12 अगस्त को भोपाल के रवीन्द्र भवन में नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में करीब 3 हजार महिला जनप्रतिनिधियों के शामिल होने का अनुमान है। सम्मेलन में स्वसहायता समूह स्टॉल लगाये जायेंगे। प्रतिनिधियों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा टीडीआर पोर्टल लांच किया जायेगा। आयुक्त नगरीय प्रशासन भरत यादव ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में एक करोड़ 75 लाख पौधरोपण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। पौधरोपण कार्यक्रम 15 सितम्बर तक चलेगा। बैठक में भोपाल नगर निगम की सड़कों पर चर्चा की गई। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि राजधानी की सड़कों का मरम्मत कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाये। भोपाल नगर निगम के पास 2020 किलोमीटर लंबाई की सड़के हैं।

स्लीमनाबाद टनल का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करें : शुक्ल

भोपाल। उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में स्लीमनाबाद टनल निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने और आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्र के नीचे टनल निर्माण करते हुए विशेष सावधानी बरती जाये। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा स्लीमनाबाद टनल निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई थी। बरगी व्यपवर्तन परियोजना से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना एवं रीवा सहित आस-पास के जिलों के कृषकों को सिंचाई और ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, प्रमुख सचिव वित्त मनीष सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

स्पेशल खबर एम्स में दुर्लभ रोग सहायता केंद्र का उद्घाटन...

समय पर लिया गया सही निर्णय दे सकता है नया जीवन : प्रो. सिंह

भोपाल(काप्र)। एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रो. अजय सिंह ने नियोनेटोलॉजी और बाल रोग ओपीडी में दुर्लभ रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क आस्था का उद्घाटन मंगलवार को किया।

इस अवसर पर प्रो. सिंह ने कहा कि एम्स में दुर्लभ रोग सहायता केंद्र का उद्घाटन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केंद्र उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस पहल से न केवल मरीजों को चिकित्सा सुविधा मिलने में आसानी होगी, बल्कि उन्हें आवश्यक संबल और जानकारी भी प्राप्त होगी। यह पहल फाइजर की सीएसआर पहल के तहत आयोजित की गई और डॉक्टर्स फॉर यू द्वारा क्रियान्वित की गई। कार्यक्रम के

दौरान, दुर्लभ रोगों के मरीजों को इलाज में मिलने वाली चुनौतियों और इस केंद्र के माध्यम से मिलने वाले समाधानों पर प्रकाश डाला। फाइज़र और डॉक्टर्स फॉर यू के प्रतिनिधियों ने अपने संगठनों की इस पहल के महत्व पर जोर दिया। एम्स भोपाल के अधिकारियों ने भी इस केंद्र के माध्यम से मरीजों को मिलने वाली बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की। हेल्पडेस्क टीम मरीजों को आवश्यक सेवा के लिए अस्पताल में आने-जाने में मदद करेगी। कागजी कार्रवाई से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को आवश्यकतानुसार यात्रा और आवास की सुविधा खोजने में सहायता करेगी। इस हेल्पडेस्क का उद्देश्य मरीजों और देखभाल करने वालों के बीच की खाई को पाटना और पात्र मरीजों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करना है, जैसा कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत अनुमोदित है, जिसके लिए संस्थान को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से 3 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है और एनपीआरडी 2021 के तहत अनुमोदित आवश्यक दवाओं की खरीद की प्रक्रिया में है।

प्रो. सिंह ने कहा कि आपातकालीन अवस्था में लिया गया एक सही निर्णय व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। पैरामेडिकल स्टॉफ के लिए नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कोर्स के उद्घाटन अवसर पर प्रो. सिंह ने कहा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले कोशिश करें कि मरीज को अधिकतम आरामदायक स्थिति में लायें। दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक पहुँचने का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान अगर सही तरीके से मरीज का प्रबंधन किया जाए तो उसका जीवन बचाया जा सकता है।

इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग केंद्र के निदेशक एवं एम्स नई दिल्ली इमरजेंसी सेंटर के प्रो. संजीव भोई ने कहा कि देश में हर 4 मिनट में एक्सीडेंट से एक जान चली जाती है ऐसे में पैरामेडिक की भूमिका बहुत अहम होती है और एक प्रशिक्षित पैरामेडिक स्टॉफ इमरजेंसी में मरीज को प्राथमिक इलाज देकर उसके जीवन की रक्षा कर सकता है।

मध्य प्रदेश में 65 फीसदी बारिश

भोपाल (काप्र)। मध्यप्रदेश में भारी बारिश का दौर अगले एक सप्ताह थमा रहेगा। मानसून ट्रफ के प्रदेश के ऊपर से निकलने और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कमजोर होने से ऐसा होगा अब तक यहां 65 फिसदी बारिश हुई है। एमपी में मानसून की एंट्री से अब तक 45 दिन हो गए इस दौरान औसत

24.4 इंच बारिश हो चुकी है जो सीजन की 65 फीसदी है। भोपाल, मंडला, सिवनी, नर्मदापुरम समेत 7 जिले ऐसे हैं, जहां पर 30 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। मंडला में सबसे ज्यादा 36.67 इंच बारिश हुई है। आईएमडी भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक डॉ दिव्या ने बताया कि मानसून ट्रफ मध्यप्रदेश के ऊपर व ईस्ट-वेस्ट ट्रफ साउथ राजस्थान से नॉर्थ केरल तक है। इस वजह से भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। एक सप्ताह तक ऐसा ही दौर रहेगा। प्रदेश में गरज-चमक की एक्टिविटी की संभावना जताई गई है। इससे आकाशीय बिजली गिरने या चमकने के मामले बढ़ेंगे। इसलिए बिजली चमकने के दौरान आईएमडी ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।